

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 876) पटना, शुक्रवार, 20 अक्तूबर 2023

सं0–14 / विविध–05 / 2021–2686(14) / स्वा० स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

9 अक्तूबर 2023

विषय:— राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—1462(14), दिनांक—16.08.2021 द्वारा राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू० 10,00,000/— (दस लाख रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्त की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 10,00,000/— (दस लाख रुपया) से ऊपर की व्यय राशि की प्रतिपूर्त्त वित्त विभाग की सहमित के उपरांत प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान किया गया है परन्तु चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा में बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रावधान नहीं किया जा सका है।

- 2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका— 6(V) में निहित प्रावधान के तहत् राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम रू० 5,00,000 / ─ (पाँच लाख रुपया) की सीमा तक की राशि की स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव को प्रदत्त है तथा रूपये 5,00,000 / ─ (पाँच लाख रुपया) से ऊपर की राशि की चिकित्सा अग्रिम के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव द्वारा स्वीकृति का प्रावधान है।
- 3. कतिपय विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका— 6(V) में निहित प्रावधान में संशोधन की अपेक्षा की जाती रही है।
- 4. उक्त प्रावधान लगभग आठ वर्ष पूर्व का है, जिसमें वर्त्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है।
- 5. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज हेतु विभागीय संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका— 6(V) में चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति को निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :--

(i)	अधिकतम रू० ८ लाख (आठ लाख रुपया) तक	प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव द्वारा।
(ii	रू० 8 लाख (आठ लाख रुपया) से ऊपर	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव द्वारा।

- 6. संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम राशि का सी०जी०एच०एस० दर पर निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तर पर की जायेगी।
- 7. चिकित्सा अग्रिम हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—946(14), दिनांक—14.08.2015 की कंडिका—6(V) इस हद तक संशोधित माना जायेगा।
- 8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतू प्रकाशित किया जाय।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 876-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in